सर्वोच्च न्यायालय की आख्या

मेसर्स ज़ोरास्टर एकेडी कंपनी

बनाम

कमिशनर ऑफ इंकम टैक्स, दिल्ली, अजमेर, राजस्थान और मध्य भारत (अब) मध्य प्रदेश

(यस. के. दास, यम. हिदायतुल्लाह और जे. सी. शाह, न्यायमूर्तिगण)

आय में कमी-संदर्भ -उच्च न्यायालय की मामले के पूरक विवरण की मांग करने की शक्ति-भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) धारा 66(4).

अपीलार्थी ने माल की आपूर्ति के लिए सरकार के साथ अनुबंध किया, और 1942-43 के निर्धारण वर्ष में 10,80,653 रुपये और निर्धारण वर्ष 1943-44 में 17,45,336 रूपये आय-कर अधिकारी द्वारा इसकी आय का आकलन किया गया था। सरकार को आपूर्ति अपीलार्थी द्वारा जयपुर के लिए की गई थी, और भुगतान चेक द्वारा किया गया था जो जयपुर में प्राप्त हुए थे। अपीलार्थी का तर्क था कि यह आय तत्कालीन कर योग्य क्षेत्रों के बाहर जयपुर में प्राप्त हुई थी। इस तर्क को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। अपीलार्थी ने तब भारतीय आय-कर अधिनियम की धारा 66 (1) के अधीन उच्च न्यायालय में निर्देश के लिए आवेदन किया और 10 दिसम्बर, 1952 के अपने आदेश द्वारा अधिकरण ने निम्नलिखित प्रश्न को उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए निर्दिष्ट किया।

"क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर भारत सरकार को की गई बिक्री के संबंध में लाभ और लाभ निर्धारिती द्वारा कर योग्य क्षेत्रों में प्राप्त किए गए थे?"

उच्च न्यायालय ने मामले के पूरक बयान के लिए मामले को न्यायाधिकरण को भेज दिया, जिसमें इस सवाल पर निष्कर्ष निकालने की मांग की गई कि "क्या चेक डाक द्वारा या हाथ से निर्धारिती फर्म को भेजे गए थे और इस मामले में निर्धारिती फर्म ने विभाग को क्या निर्देश दिए थे। अपीलार्थी ने न्यू जहांगीर वकील मिल के मामले, [1960] 1 यस.सी.आर. 249. में निर्णय पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाया।

अभिनिर्धारित, किया गया कि ऐसे मामलों में जांच यह देखने के लिए होनी चाहिए कि क्या अधिकरण द्वारा विनिश्चय किया गया प्रश्न इस बात को स्वीकार करता है कि नए बिंदु पर विचार करना उसका अभिन्न अंग या आनुषंगिक भाग है। पूरक कथन जिसे अधिकरण को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

गया है, वह अधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए और/या पाए गए तथ्यों से उत्पन्न होना चाहिए और नए साक्ष्य के लिए द्वार नहीं खोलना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, यह *अभिनिर्धारित* किया गया कि इस मामले में तैयार किया गया प्रश्न इस जांच को सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त था कि क्या कोई अनुरोध, व्यक्त या निहित था, कि पहाड़ियों की राशि का भुगतान चेक द्वारा किया जाए ताकि मामले को इस न्यायालय के आदेश के भीतर लाया जा सके *ऑगले ग्लास वर्क्स मामला, [1955] 1 यस.सी.आर. 185 या जगदीश मिल्स मामला, [1960] 1 यस.सी.आर. 236.*

इसके विपरीत उच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट रूप से कही गई किसी भी बात के अभाव में, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि दिया गया निर्देश अनिवार्य रूप से नए साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगा क्योंकि यह *न्यू जहांगीर वकील मिल्स* मामले द्वारा निषिद्ध किया गया है।

द न्यू जहांगीर वकील मिल्स लिमिटेड बनाम कमिशनर ऑफ इंकम टैक्स [1960] 1 यस.सी.आर. 249, भिन्न। जगदीश मिल्स लिमिटेड बनाम कमिशनर ऑफ इंकम टैक्स, [1960] 1 यस.सी.आर. 236, केशव मिल्स कंपनी लिमिटेड, बनाम कमिशनर ऑफ इंकम टैक्स, [1950] 18 अल.टी.आर. 407, सर शोभा सिंह बनाम कमिशनर ऑफ इंकम टैक्स, [1950] 1 यस.आई.टी.आर. 998, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड बनाम कमिशनर ऑफ इंकम टैक्स, [1952] 21 आई.टी.आर. 82. कमिशनर ऑफ इंकम टैक्स बनाम ओगल-ग्लास वर्क्स लिमिटेड, [1955] ।1 यस.सी.आर. 185, कमिशनर ऑफ इंकम टैक्स बनाम किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड, [1954] 25 आई.टी.आर. 547 और श्रीमती कुसुमबर्न डी.महादेविया, बॉम्बे बनाम कमिशनर ऑफ इंकम टैक्स, बॉम्बे, [1960] 3 यस.सी.आर. 417, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1958 की सिविल अपील संख्या 30.

पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24 मार्च, 1955 से 1953 की सिविल संदर्भ संख्या 3.

अपीलार्थियों के लिए *गोपाल सिंह।*

प्रत्यर्थी के लिए *के. एन. राजगोपाल शास्त्री और डी. गुप्ता।*

1960, 17 अगस्त न्यायालय का निर्णय दिया गया था द्वारा **हिदायतुल्लाह न्यायमूर्ति-**

यह अपील, इस न्यायालय की विशेष अनुमति द्वारा, पंजाब उच्च न्यायालय के 24 मार्च, 1955 के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 66 (4) के अधीन कार्य करने के आशय से आयकर अपीलीय अधिकरण से मामले का पूरक बयान मांगता है। इस न्यायालय द्वारा दी गई विशेष अनुमति इस प्रश्न तक सीमित है कि क्या उच्च न्यायालय के पास इस मामले में पूरक बयान की मांग करने का अधिकार क्षेत्र था।

निर्धारिती, मेसर्स एस. ज़ोरास्टर एंड कंपनी, जयपुर में तीन भागीदार होते हैं। उनमें से दो एक संयुक्त हिंदू परिवार के सह-भागीदार हैं, और तीसरा एक अजनबी है। उन्होंने जून, 1940 में कंबल, फलेट और अन्य ऊनी वस्तुओं के निर्माण और बिक्री के लिए इस साझेदारी का गठन किया था। 16 मार्च, 1944 को साझेदारी का एक विलेख भी निष्पादित किया गया था। निर्धारिती ने माल की आपूर्ति के लिए सरकार के साथ अनुबंध किया, और 1942-43 के निर्धारण वर्ष में, 10,80,658-0-0 रुपये और निर्धारण वर्ष 1943-44 में, 17,45,336-0-0 रुपये को आयकर अधिकारी, ठेकेदार सर्कल, नई दिल्ली द्वारा इसकी आय के रूप में आंका गया था। सरकार को आपूर्ति निर्धारिती द्वारा जयपुर के लिए की गई थी, और भुगतान चेक द्वारा किया गया था जो जयपुर में प्राप्त हुए थे और संयुक्त हिंदू परिवार के पक्ष में समर्थन किया गया था, जो निर्धारिती के बैंकर के रूप में काम करते थे। निर्धारिती का तर्क था कि यह आय तत्कालीन कर योग्य क्षेत्रों के बाहर जयपुर में प्राप्त की गई थी। इस तर्क को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

तब निर्धारिती ने भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 66 (1) के अधीन उच्च न्यायालय में निर्देश के लिए आवेदन किया और 10 दिसंबर, 1952 के अपने आदेश द्वारा आयकर अपीलीय अधिकरण ने उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रश्न निर्दिष्ट कियाः

"क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर भारत सरकार को की गई बिक्री के संबंध में लाभ और प्राप्ति निर्धारिती द्वारा कर योग्य क्षेत्रों में प्राप्त किए गए थे?"

अधिकरण ने मामले के बयान में इस प्रकार कहा थाः

"भुगतान भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे शाखा के चेक द्वारा किया गया था। ये चेक जयपुर में प्राप्त हुये थे।"

यह इंगित किया जा सकता है कि निर्धारिती और भारत सरकार के बीच बिक्री के अनुबंध में, भुगतान की प्रणाली को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित खंड शामिल किया गया थाः

"21 भुगतान की प्रणालीः- जब तक कि क्रेता और ठेकेदार के बीच अन्यथा सहमति न हो, तब तक दुकानों की डिलीवरी के लिए भुगतान मुख्य लेखा परीक्षक, भारतीय भंडार विभाग, नई दिल्ली द्वारा

भारत में किसी सरकारी खजाने में या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक की किसी शाखा में चेक द्वारा किया जाएगा जो सरकारी व्यवसाय का लेन-देन करता है।"

संदर्भ से निपटने में, उच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम की धारा 66 (4) के तहत एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था, ".....अपीलीय न्यायाधिकरण यह पता लगाने के लिए कि क्या चेक डाक द्वारा या हाथ से निर्धारिती फर्म को भेजे गए थे और इस मामले में निर्धारिती फर्म ने विभाग को क्या निर्देश दिए थे।"

इसके बाद उच्च न्यायालय ने इंगित के तर्ज पर मामले के पूरक बयान के लिए मामले को न्यायाधिकरण को भेज दिया। इस आदेश पर *द न्यू जहांगीर वकील मिल्स लिमिटेड बनाम कमिशनर ऑफ इंकम टैक्स (1)* में इस न्यायालय के निर्णय के अधिकार पर सवाल उठाया गया है, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि यह पूरी तरह से इस मामले को शामिल करता है। उस मामले में भी; बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने मामले के पूरक बयान के लिए कहा था, और इस न्यायालय द्वारा यह फैसला सुनाया गया था कि उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था।

इस प्रश्न से निपटने से पहले थोड़ा पीछे जाना आवश्यक है, और *न्यू जहांगीर वकील मिल्स मामले (1)* और *जगदीश मिल्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (2)* से पहले तय किए गए कुछ मामलों का संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक है, जिन पर इस मामले में भरोसा किया गया है। *के. पी. शव मिल्स को. लिमिटेड बनाम कमिशनर ऑफ इंकम टैक्स (1)* में बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने मामले के पूरक बयान के लिए कहा, लेकिन यह विचार व्यक्त किया कि यदि किसी लेनदार द्वारा चेक प्राप्त किया गया था, एक ब्रिटिश इंडियन बैंक में और उसने चेक को वसूली के लिए अपने बैंक को दिया, बैंक को अपने एजेंट के रूप में माना जाना चाहिए और यह कि कर योग्य क्षेत्र में चेक की राशि की प्राप्ति पर लेनदार को कर योग्य क्षेत्र में प्राप्त किया जाना चाहिए, भले ही वह इसके बाहर हो। *सर सभा सिंह बनाम कमिशनर ऑफ इंकम टैक्स (2)* वाले मामले में पंजाब उच्च न्यायालय ने कहा था कि जहां चेक संग्रह के प्रयोजनों के लिए किसी बैंक को दिए गए थे, वहां धन की रसीद उस स्थान पर थी, जहां वह बैंक था, जिस पर चेक निकाले गए थे।

इन विचारों को आगे बढ़ाया गया और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दो अन्य मामलों में लागू किया गया। वे हैं *किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड बनाम कमिशनर ऑफ इंकम टैक्स (3)* और *ओगले ग्लास वर्क्स लिमिटेड बनाम कमिशनर ऑफ इंकम टैक्स (4)* इन दोनों मामलों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब तक प्राप्तकर्ता स्पष्ट रूप से डाकघर को अपने अभिकर्ता के रूप में गठित नहीं करता है, केवल चेक की पोस्टिंग डाकघर को प्राप्तकर्ता का अभिकर्ता नहीं बनाती है, और यह कि चेक की राशि भी उस स्थान पर प्राप्त की गई थी जहां चेक प्राप्त किया गया था। *किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड बनाम कमिशनर*

ऑफ इंकम टैक्स (3) के मामले में यह *अभिनिर्धारित* किया गया था कि केवल दिल्ली में चेक की पोस्टिंग दिल्ली में चेक की प्राप्ति के समान नहीं थी, क्योंकि प्राप्तकर्ता ने सरकार से डाक द्वारा चेक भेजने का अनुरोध नहीं किया था। *ओगले ग्लास वर्क्स मामले (4)* में बंबई उच्च न्यायालय ने अधिकरण से मामले का एक पूरक विवरण माँगा कि क्या निर्धारिती द्वारा कोई स्पष्ट अनुरोध किया गया था कि चेक उसे डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए, और यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि ऐसा कोई स्पष्ट अनुरोध नहीं था, इसलिए धन की रसीद उस स्थान पर नहीं थी जहां चेक पोस्ट किया गया था, बल्कि उस स्थान पर थी जहां धन प्राप्त किया गया था।

इस न्यायालय द्वारा बंबई उच्च न्यायालय के अंतिम दो निर्णयों को उलट दिया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भुगतानकर्ता को चेक द्वारा राशि "प्रेषित" करने की सूचना देना डाकघर का प्राप्तकर्ता के अभिकर्ता के आयुक्त के रूप में नामांकन के लिए पर्याप्त थाः *कमिशनर ऑफ इंकम टैक्स बनाम ओगले ग्लास वर्क्स लिमिटेड (1) और कमिशनर ऑफ इंकम टैक्स बनाम किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड(2)* बाद में इस अदालत ने *जगदीश मिल्स (3)* मामले में इस सिद्धांत को और आगे बढ़ा दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां विधेयकों का समर्थन था 'सरकार को देय राशि का भुगतान चेक द्वारा करना चाहिए' और चेक बिना किसी शर्त के पूर्ण संतुष्टि में प्राप्त किए गए थे, यह इस न्यायालय के *ओगले ग्लास वर्क्स लिमिटेड (1)* में नियम के आवेदन के उद्देश्य के लिए एक पर्याप्त निहित अनुरोध का निर्माण करता है।

जगदीश मिल्स मामला (3) और *न्यू जहांगीर वकील मिल्स मामला (4)* का फैसला इसी अदालत ने उसी दिन किया था। बाद के मामले में, विभाग को एक अनिवासी कंपनी के साथ काम करना पड़ा, जो हर भौतिक समय पर, भारतीय राज्यों में से एक भावनगर में स्थित थी। सरकार को आपूर्ति के भुगतान के लिए चेक ब्रिटिश भारत से भावनगर भेजे गए थे। विभाग ने मामले में तर्क दिया कि हालांकि चेक भावनगर में प्राप्त किए गए थे, लेकिन वास्तव में, उन्हें ब्रिटिश भारत में नकद किया गया था और इस तरह के नकदीकरण तक, आय को प्राप्त नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ब्रिटिश भारत में नकदीकरण पर, आय की प्राप्ति भी ब्रिटिश भारत में थी। अधिकरण ने कहा कि भावनगर में चेक प्राप्त होने के बाद वहां भी आय प्राप्त हुई थी। ऐसा करते हुए अधिकरण ने *किर्लोस्कर ब्रदर्स (5)*मामले में बॉम्बे के फैसले का पालन किया हालांकि, न्यायाधिकरण ने कहा कि यदि इस न्यायालय में अपील के तहत बॉम्बे के दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रखा जाता है, तो इस बात की जांच करनी होगी कि क्या अहमदाबाद में मिल्स के बैंकरों ने चेक पर देय राशि एकत्र करने के लिए मिल्स के एजेंटों के रूप में काम किया था। यह सवाल कि क्या मिल्स के अनुरोध पर, व्यक्त या निहित, ब्रिटिश भारत से भावनगर में चेक की पोस्टिंग से कोई फर्क पड़ा, मामला बॉम्बे के उच्च न्यायालय में पहुंचने से पहले किसी भी स्तर पर विचार नहीं किया गया था। यह स्पष्ट रूप से इस न्यायालय द्वारा इन शब्दों में पाया गयाः

"सभी भौतिक चरणों में राजस्व द्वारा आग्रह किया गया एकमात्र आधार यह था कि क्योंकि व्यापारियों या सरकार से हमें जो राशि प्राप्त हुई थी, वह ब्रिटिश भारत में बैंकों से प्राप्त चेक द्वारा प्राप्त की गई थी,

जो अंततः ब्रिटिश भारत में भुनाया गया था, यह नहीं कहा जा सकता था कि धन भावनगर में प्राप्त हुआ था, हालांकि चेक वास्तव में भावनगर में प्राप्त हुए थे।"

अधिकरण ने *ओगले ग्लास वर्क्स मामले (1) और किर्लोस्कर ब्रदर(2)* के मामले में इस अदालत के फैसले तक संदर्भ को रोक दिया था। यह देखने के बाद भी कि उन दो मामलों में चेक द्वारा भुगतान के लिए अनुरोध पोस्ट द्वारा भेजा जाना है सभी अंतर, न्यायाधिकरण ने इस पहलू को शामिल करने के लिए मामले या प्रश्न के अपने बयान को फ्रेम नहीं किया, क्योंकि मामले के उस पहलू पर पहले कभी विचार नहीं किया गया था। इस प्रकार, निर्दिष्ट प्रश्न भावनगर में चेक की प्राप्ति के कानूनी प्रभाव तक सीमित था, इस तथ्य के विज्ञापन के बिना कि क्या चेक मिलों के अनुरोध, व्यक्त या निहित, पर डाक द्वारा भेजे गए थे। प्रश्न तैयार किया गया थाः "क्या भावनगर में चेक की प्राप्ति भावनगर में बिक्री आय की प्राप्ति के बराबर है?"

प्रश्न के रूप में तैयार किया गया और उसके साथ दिए गए बयान ने विवाद में एकमात्र बिंदु लाया जिस पर तब तक न्यायाधिकरण और कर अधिकारियों द्वारा विचार किया गया था। जिनके द्वारा मामले की सुनवाई की गई थी, उच्च न्यायालय ने *किर्लोस्कर ब्रदर्स (2)* और *ओगले ग्लास वर्क्स (1)* मामलों के एजेंट से इस पर विचार करने की इच्छा व्यक्त की। इसने मामले के पूरक बयान की मांग की। ऐसा करते हुए, उच्च न्यायालय विवाद के दायरे से परे चला गया क्योंकि यह तब तक मौजूद था और मामले का बयान और प्रश्न भी। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण को इस प्रकार निर्देश दियाः

"न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष पर कि सभी चेक भावनगर में प्राप्त हुए थे, न्यायाधिकरण यह पता लगाने के लिए कि इन चेकों का कौन सा हिस्सा डाक द्वारा प्राप्त हुआ था, 'क्या निर्धारिती द्वारा कोई अनुरोध किया गया था, व्यक्त या निहित, कि जो राशि इन चेकों का विषय है, उसे डाक द्वारा भावनगर को प्रेषित किया जाना चाहिए।"

इस आपत्ति को खारिज करते हुए कि ऐसी जांच न्यायाधिकरण द्वारा तय किए गए बिंदु से अलग थी और इसके लिए नए साक्ष्य की आवश्यकता हो सकती है, उच्च न्यायालय ने खुद को यह कहते हुए उचित ठहरायाः "लेकिन हम आवश्यक जांच को बंद नहीं कर सकते हैं जो हमारे अपने दृष्टिकोण से भी आवश्यक है ताकि हमें संदर्भ में उठाए गए प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दिया जा सके। यह नहीं भूलना चाहिए कि आयकर अधिनियम की धारा 66 (4) के तहत हमें पक्षों के आचरण से स्वतंत्र रूप से न्यायाधिकरण को आगे के तथ्यों को बताने का निर्देश देने का अधिकार है ताकि हम अपने स्वयं के सलाहकार अधिकार क्षेत्र का उचित रूप से प्रयोग कर सकें।"

इस न्यायालय ने बताया कि उच्च न्यायालय ने भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 66 (4) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।

यह कहा गया था: "यदि वास्तव में निर्दिष्ट प्रश्न पक्षों के बीच वास्तविक मुद्दे को स्पष्ट रूप से सामने नहीं लाता है, तो उच्च न्यायालय प्रश्न को फिर से तैयार कर सकता है ताकि न्यायाधिकरण के समक्ष वास्तव में उत्तेजित मामला उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जा सके। लेकिन धारा 66 (4) उच्च न्यायालय को विधि का नया प्रश्न उठाने के लिए सक्षम नहीं करती है जो अधिकरण के आदेश से उत्पन्न नहीं होता है और अधिकरण को इस नए प्रश्न का निर्धारण करने के लिए आवश्यक नए और आगे के तथ्यों की जांच करने का निर्देश देता है जो धारा 66 (1) या धारा 66 (2) के तहत उसे निर्दिष्ट नहीं किया गया था और अधिकरण को मामले का पूरक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देता है।"

यह भी बताया गया कि न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए और/या पाए गए तथ्य ही कानून के प्रश्न का आधार हो सकते हैं, जिसे न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न कहा जा सकता है। इस प्रकार मामले ने धारा 66 (4) के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता के लिए दो सीमाएं निर्धारित कीं और वे थीं कि सलाहकार अधिकारिता (क) अभिलेख पर तथ्यों और/या अधिकरण द्वारा पाए गए तथ्यों तक सीमित थी और (ख) वह प्रश्न जो अधिकरण के आदेश से उत्पन्न होगा। इस न्यायालय द्वारा यह इंगित किया गया था कि उच्च न्यायालय रिकॉर्ड को बढ़ाने की दृष्टि से नए तथ्यों की नए सिरे से जांच का आदेश देने के लिए खुला नहीं था और आगे यह कि यह उच्च न्यायालय के लिए कानून के प्रश्न का निर्णय करने के लिए समान रूप से स्वतंत्र नहीं था, जो न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न नहीं हुआ था। अधिकरण द्वारा तैयार किए गए प्रश्न की तुलना उस प्रश्न से करके इसे स्पष्ट किया गया था जिसे उच्च न्यायालय तय करना चाहता था। जबकि न्यायाधिकरण ने केवल इस प्रश्न का उल्लेख किया थाः

"क्या भावनगर में चेक की प्राप्ति भावनगर में बिक्री आय की प्राप्ति के बराबर है? "

उच्च न्यायालय का जो निर्णय लेने का इरादा था वह थाः

"क्या अपीलार्थी के अनुरोध पर ब्रिटिश भारत में चेक की पोस्टिंग, ब्रिटिश भारत में बिक्री आय की प्राप्ति के बराबर है?"

ये दो पूरी तरह से अलग-अलग प्रश्न थे, और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय किसी ऐसे मामले का निर्णय नहीं कर सकता जो अधिकरण द्वारा तय किए गए मामले से अलग हो, और न ही इस नए मामले से संबंधित मामले के बयान की मांग कर सकता है।

जहाँगीर वकील मिल्स मामले (1) में निर्धारित प्रस्ताव को इस न्यायालय के एक अन्य मामले से समर्थन मिलता है जिसका निर्णय हाल ही में लिया गया है। *के. उसुम्बेन डी. महादेविया बनाम कमिशनर ऑफ इंकम टैक्स, बी. सी. एन. बी. (2)* में यह कहा गया थाः

"हमारी राय में, निर्धारिती की आपत्ति अच्छे आधारों पर आधारित है। न्यायाधिकरण ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या रियायत आदेश प्राप्तकर्ता पर लागू होता है। इसने आकलन के सवाल का फैसला इस आधार पर किया कि आय बड़ौदा में नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत में उत्पन्न हुई थी। बंबई उच्च न्यायालय ने मामले के उस पहलू को नहीं छुआ है। दूसरी ओर, उत्तरार्द्ध ने विचार किया है कि क्या रियायत आदेश निर्धारिती पर लागू होता है, एक ऐसा मामला जिसे न्यायाधिकरण ने छुआ ही नहीं है। इस प्रकार, यद्यपि जहां तक मूल्यांकन का संबंध है, परिणाम समान है, निर्णय के आधार पूरी तरह से अलग हैं।"

आय-कर अधिनियम की धारा 66, जो उच्च न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करती है, केवल अधिकरण के आदेश से उत्पन्न विधि के प्रश्न के निर्देश की अनुमति देती है। यह उच्च न्यायालय को इस तरह के आदेश से उत्पन्न नहीं होने वाले विधि के एक अलग प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है। यह संभव है कि कानून के एक ही प्रश्न के समाधान के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण शामिल हो सकते हैं, और उच्च न्यायालय सभी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रश्न को बढ़ा सकता है। लेकिन सवाल अभी भी वही होना चाहिए जो न्यायाधिकरण के समक्ष था और उसके द्वारा तय किया गया था। यह पूरी तरह से अलग सवाल नहीं होना चाहिए जिस पर न्यायाधिकरण ने कभी विचार नहीं किया।

इससे यह पता चलता है कि ऐसे मामलों में जांच यह देखने के लिए होनी चाहिए कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा तय किया गया प्रश्न नए बिंदु के विचार को एक अभिन्न या एक आकस्मिक भाग के रूप में स्वीकार करता है। फिर भी, जो पूरक कथन अधिकरण को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, वह अधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए और/या पाए गए तथ्यों से उत्पन्न होना चाहिए, और नए साक्ष्य के लिए द्वार नहीं खोलना चाहिए। तथ्य यह है कि *ओगले ग्लास वर्क्स मामले (1)* में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने *जहांगीर वकील मिल्स(2)* मामले की तरह ही पूरक बयान मांगा था और इस न्यायालय ने नए मामले को खारिज नहीं किया था, वर्तमान मामले में निर्धारिती की मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय की अधिकारिता पर सवाल नहीं उठाया गया था, जैसा कि *जहांगीर वकील मिल्स* मामले में किया गया था, या यहां किया गया है। इस प्रकार हमें यह देखना होगा कि क्या इस मामले में वह प्रश्न जो तय किया गया था और जिसे उच्च न्यायालय को भेजा गया है, अपील के तहत आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा इंगित की गई तर्ज पर पूरक बयान के लिए मामले की वापसी को स्वीकार करता है।

शुरुआत में ही इस मामले में कानून के सवाल में अंतर दिखाई देता है और एक तरफ ओगल ग्लास वर्क्स मामले (1) और दूसरी तरफ जहांगीर वकील मिल मामले (2) में विधि के सवाल में अंतर दिखाई देता है। 'पहले दो मामलों में, सवाल बहुत व्यापक है, जबकि बाद वाले में यह बेहद संकीर्ण है। इसे तीन प्रश्नों को साथ-साथ नीचे लिखे अनुसार रखकर देखा जा सकता हैः

जहांगीर वकील मिल्स मामला (1) "क्या भावनगर में चेक की प्राप्ति भावनगर में बिक्री आय की प्राप्ति के बराबर है?"

ओगल ग्लास वर्क्स केस (2) "क्या मामले के तथ्यों पर, भारत सरकार को की गई बिक्री के संबंध में आय, लाभ और प्राप्ति अधिनियम की धारा 4 (1) (क) के अर्थ के भीतर ब्रिटिश भारत में प्राप्त किए गए थे?"

यह मामलाः "क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर भारत सरकार को की गई बिक्री के संबंध में लाभ और प्राप्ति निर्धारिती द्वारा कर योग्य क्षेत्रों में प्राप्त किए गए थे?"

यह मामलाः इस प्रकार यह बहुत स्पष्ट है कि इस मामले में तैयार किए गए प्रश्न में इस बात की जांच शामिल हो सकती है कि क्या कोई अनुरोध, व्यक्त या निहित था, कि बिलों की राशि का भुकतान चेक द्वारा ताकि मामले को इस अदालत के आदेश *ओगले ग्लास वर्क्स केस (2)* या *जगदीश मिल्स केस (3)* के भीतर लाया जा सके, इस न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय की अधिकारिता की पहली सीमा के रूप में इस प्रकार निरधारित की है कि उच्च न्यायालय द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 66 (4) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में इसे पार नहीं कर सकता है, यह प्रश्न इस वैकल्पिक दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए काफी व्यापक है कि यदि बिलों के तहत देय राशि को चेक द्वारा भेजने का कोई अनुरोध, व्यक्त या निहित था, तो डाकघर निर्धारिती का एजेंट होगा, और जब चेक पोस्ट किए गए थे तो आय कर योग्य क्षेत्र में प्राप्त हुई थी।

अगला प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने दूसरी सीमा का उल्लंघन किया है जो धारा 66 (4) में निहित है अर्थात् यह प्रश्न अधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए और/या पाए गए तथ्यों से उत्पन्न होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि

"अपीलीय अधिकरण के लिए यह पता लगाना आवश्यक होगा कि क्या चेक डाक द्वारा या हाथ से निर्धारिती फर्म को भेजे गए थे और उस मामले में निर्धारिती फर्म ने विभाग को क्या निर्देश दिए थे।"

अगर अधिकरण को रिकॉर्ड पर नए सबूतों को स्वीकार करने के लिए एक नई जांच करनी है, तो यह निर्देश *जहांगीर वकील मिल्स (1)* मामले में इस अदालत के फैसले के खिलाफ है। यदि, तथापि, निर्देश की व्याख्या इस अर्थ में की जाती है कि अधिकरण को निष्कर्ष देने में स्वयं को स्वीकार किए गए और/या उसके द्वारा पाए गए तथ्यों तक सीमित रखना चाहिए, तो निर्देश को उच्च न्यायालय की अधिकारिता से अधिक बताया नहीं जा सकता है। यह बेहतर होता यदि उच्च न्यायालय अधिकरण के समक्ष मामले के अभिलेख तक ही सीमित निर्देश देता; लेकिन, इसके विपरीत स्पष्ट रूप से कुछ भी न

होने पर, हम यह नहीं मान सकते कि निर्देश अनिवार्य रूप से नए साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगा। कम से कम, अब ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहांगीर वकील मिल्स मामले *(1)* ने नए सबूतों को स्वीकार करने पर रोक लगा दी है।

हमारी राय में, वर्तमान मामला *जहांगीर बनाम वकील मिल्स मामले (1)* में नियम के अंतर्गत नहीं आता है और यह अलग है। परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाती है और लागत के साथ खारिज कर दी जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

मेसर्स ज़ोरास्टर एकेडी कंपनी बनाम कमिशनर ऑफ इंकम टैक्स , दिल्ली, अजमेर, राजस्थान और मध्य भारत (अब) मध्य प्रदेश

श्री चंद्रकान्त शुक्ला की देख रेख में अधिवक्ता मयंक कुमार सिंह द्वारा अनुवादित।